



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032025-261715
CG-DL-E-19032025-261715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1222]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946

No. 1222]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

का.आ. 1235(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रातापानी और सिंधोरी वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2605(अ), तारीख 11 अगस्त, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2605(अ), तारीख 11 अगस्त, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2605(अ), तारीख 11 अगस्त, 2017 को प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“5. मॉनीटरी समिति. – केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक मॉनीटरी समिति का गठन करेगी, अर्थात्: -

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| (i) | संभागीय आयुक्त, भोपाल- अध्यक्ष, पदेन | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा- सदस्य; | सदस्य; |
| (iii) | पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर हर तीन साल में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ- सदस्य; | सदस्य; |
| (iv) | मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य, पदेन; | सदस्य, पदेन; |
| (v) | मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामांकित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ- सदस्य; | सदस्य, पदेन; |
| (vi) | मुख्य वन संरक्षक, भोपाल - सदस्य, पदेन; | सदस्य, पदेन; |
| (vii) | जिला कलेक्टर, रायसेन- सदस्य, पदेन; | सदस्य, पदेन; |
| (viii) | अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, रायसेन - सदस्य, पदेन; | सदस्य, पदेन; |
| (ix) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन- पदेन सदस्य; | सदस्य, पदेन; |
| (x) | नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का जिला अधिकारी- सदस्य, पदेन; | सदस्य, पदेन; |
| (xi) | प्रभागीय वनाधिकारी, औबेदुल्लागंज | सदस्य सचिव, पदेन। |

6. मॉनीटरी समिति के कार्य:- (1) मॉनीटरी समिति, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों की, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है, संवीक्षा करेगी, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुज्ञापत्र के लिए, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों की, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसी प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट है वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (3) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (4) मॉनीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, समिति को उसके विचार-विमर्श में सहायता के लिए, विभाग से किसी प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों के किसी प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) मॉनीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संगलग्न उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार, मॉनीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।”

[फा.सं. 25/35/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में विस्तृत का.आ. 2605(अ), तारीख 11 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2025

S.O. 1235(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Ratapani and Singhori Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2605(E), dated the 11th August, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2605(E), dated the 11th August, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2605(E), dated the 11th August, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted namely: -

“5. **Monitoring Committee.** -The Central Government hereby constitutes a Monitoring committee consisting of the following persons, namely: -

- (i) Divisional Commissioner, Bhopal– Chairman, *ex officio*
- (ii) One representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh from time to time every three years– Member;
- (iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh from time to time every three years– Member;
- (iv) Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board – Member , *ex officio*;
- (v) An expert in Biodiversity to be nominated by the State Govt of Madhya Pradesh from time to time every three years– Member;
- (vi) Chief conservator of Forests , Bhopal – Member , *ex officio*;
- (vii) District Collector, Raisen– Member, *ex officio*;
- (viii) Superintending Engineer, Public Health Dept. Raisen – Member, *ex officio*;
- (ix) Chief Executive Officer of Zilla Panchayat, Raisen– Member, *ex officio*;
- (x) District Officer of Town and Country planning Department– Member, *ex officio*;
- (xi) Divisional Forest Officer, Obedullaganj – Member-Secretary, *ex officio*.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”

[F. No. 25/35/2016-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2605(E), dated the 11th August, 2017.